



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

4 श्रावण 1933 (श०)  
(सं० पटना 364) पटना, मंगलवार, 26 जुलाई 2011

---

आपदा प्रबंधन विभाग

-----  
अधिसूचनाएं

25 जुलाई 2011

शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली, 2011

सं० 1/आ०प्र०यो०-12/2010-2388/आ०प्र०—चूँकि राज्य में रहने वाले निर्धन, बूढ़े, शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य आघातयोग्य/ कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भूखमरी की घटनाओं की रोकथाम करना तथा समाज के कमजोर/ आघात योग्य वर्गों को भूखमरी की स्थिति में खाद्यान्न की आसान पहुँच सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है, और चूँकि, समाज के आघातयोग्य वर्गों का राज्य के भौतिक संसाधनों पर वैधानिक स्वामित्व एवं नियंत्रण है। इसलिए बिहार के राज्यपाल भारत संविधान के अनुच्छेद 39(ख) के अधीन निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ—

- (1) यह नियमावली “शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली 2011” कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा

जब तक कि, संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में

- (i) “अंचल अधिकारी” से अभिप्रेत है राज्य सरकार के द्वारा इस रूप में पदाभिहित अधिकारी।
- (ii) “प्रखण्ड विकास पदाधिकारी” से अभिप्रेत है राज्य सरकार के द्वारा इस रूप में पदाभिहित अधिकारी।
- (iii) “आपदा प्रबंधन विभाग” से अभिप्रेत है बिहार सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग।
- (iv) “खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग” से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

- (v) “समाज कल्याण विभाग” से अभिप्रेत है बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग
- (vi) “जिला दण्डाधिकारी” से अभिप्रेत है जिला के जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता।
- (vii) “निधि” से अभिप्रेत है इस योजना के अधीन गठित निधि,
- (viii) “मुखिया” से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में कार्यरत व्यक्ति,
- (ix) “नियमावली” से अभिप्रेत है शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली, 2011,
- (x) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है बिहार सरकार,
- (xi) “वार्ड पार्षद” से अभिप्रेत है किसी नगरीय वार्ड का पार्षद जैसा कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अधीन परिभाषित है।
- (xii) “कल्याणकारी योजनाएँ” से अभिप्रेत है राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा बिहार राज्य में क्रियान्वयन के अधीन केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ,
- (xiii) “योजना” से अभिप्रेत है शताब्दी अन्न कलश योजना।

2. इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो बिहार राज्य की आम भाषा में समझे जाते हैं।

**3. निधि/कोष का गठन एवं प्रबंधन-** (1) राज्य शताब्दी अन्न कलश निधि के नाम एवं शैली से राज्य स्तर पर राज्य निधि नामक एवं सभी जिलों में जिला शताब्दी अन्न कलश निधि नामक जिला निधि का गठन, इस योजना अधीन कमजोर/ आघातयोग्य वर्गों को दिये जाने वाले खाद्यान्नों के भुगतान करने के प्रयोजनार्थ किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अधीन आवंटित सभी राशि इस निधि में रखी जाएगी। इस निधि में आम जनता को भी नगद अंशदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(3) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति राज्य निधि का प्रबंधन करेगी। हालाँकि समाज कल्याण विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव/ प्रधान सचिव समिति की बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित होंगे।

(4) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार जिला निधि का प्रबंधन करेगा। हालाँकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ अपर जिला दण्डाधिकारी(आपूर्ति) तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित होंगे।

(5) बिहार सरकार प्रारंभिक निधि के रूप में ₹0 10 करोड़ राज्य निधि को आवंटित करेगी तथा राज्य कार्यकारिणी समिति के परामर्श से, वार्षिक आवंटन करेगी। इस प्रकार से किये गये आवंटन, आपदा प्रबंधन विभाग के वार्षिक गैर-योजना बजट का भाग होगा।

(6) राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा निर्णीत मानदण्डों के अनुसार राज्य निधि से कितनों में आवंटन जिलों को दिया जायेगा। यद्यपि कि अगली किश्त पूर्ववर्ती किश्त के 75 प्रतिशत व्यय होने के उपरान्त ही विमुक्त की जायेगी।

**4. निधि का लेखा एवं अंकेक्षण:-**(1) इस निधि को संबंधित निधि के नाम से खोले गए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता में रखा जाएगा तथा इससे मिलने वाली ब्याज भी इसी निधि का भाग होगी।

(2) राज्य एवं जिला निधि के लेखा का संधारण क्रमशः आपदा प्रबंधन विभाग एवं संबंधित जिला पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा।

(3) इस निधि का वार्षिक अंकेक्षण, वित्त विभाग के अंकेक्षण शाखा द्वारा किया जाएगा तथा प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग के अंकेक्षण शाखा द्वारा किया जाएगा तथा प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग को सौंपी जाएगी।

**5. इस नियमावली अधीन मुखिया, वार्ड पार्षद, पंचायत वार्ड सदस्य एवं अन्य पंचायत स्तरीय कृत्यकारियों के कर्तव्य:-** (1) ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया, वार्ड पार्षद, पंचायत वार्ड सदस्य तथा अन्य पंचायत स्तरीय कृत्यकारियों तथा नगर क्षेत्रों में संबंधित वार्ड पार्षद का यह कर्तव्य होगा कि वे यथाशक्ति अपने क्षेत्राधिकार में निवास कर रहे गरीब, बूढ़े, शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य आघातयोग्य वर्गों / परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता के बारे में सतर्क/ चौकस रहें। वे उन आघातयोग्य परिवारों, जो संसाधन विहीन हों तथा जिनके पास आजीविका का कोई

साधन न हो या जो, उनके नियंत्रण से परे हालातों के कारण, स्थायी या अस्थायी रूप से आजीविका कमाने में अक्षम बना दिये गये हों, के लिए को खाद्यान्न की उपलब्धता पर विशेष चौकसी/ सतर्कता रखेंगे।

(2) इस नियमावली में निर्देशित पंचायत स्तरीय कृत्यकारियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, जन सेवक आदि शामिल होंगे।

(3) यथा स्थिति मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य या वार्ड पार्षद को चौकसी बरतने में अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत सरकारी क्षेत्राधिकारी से सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। उन्हें सिविल सोसाईटी संगठनों से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

(4) किसी आघातयोग्य/परिवार की भूखमरी की दशा की सूचना प्राप्त होते ही यथा स्थिति, मुखिया, वार्ड पार्षद, ग्राम पंचायत के सदस्य या उपर्युक्त कृत्यकारी तत्परता से जाँच करेंगे तथा यथास्थिति मुखिया, वार्ड पार्षद या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को एक प्रतिवेदन सौंपेंगे।

**6. शताब्दी अन्न कलश योजना:-** (1) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग एवं संबंधित जिला पदाधिकारी से परामर्श से राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक पंचायत में एक नामनिर्दिष्ट जनवितरण प्रणाली विक्रेता की दूकान में एक क्वींटल गेहूँ/चावल का चक्रीय स्टॉक संधारित करेगा। नगरीय क्षेत्र में जिला दण्डाधिकारी ऐसे निर्दिष्ट जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को चिन्हित करेंगे जहाँ खाद्यान्नों का चक्रीय स्टॉक का भण्डारण किया जा सके।

(2) राज्य खाद्य निगम के गोदामों से चक्रीय स्टॉक के उठाव के लिए भुगतान संबंधित जन वितरण प्रणाली की दूकान के मालिक द्वारा किया जायेगा।

(3) भूखमरी की दशा का सामना कर रहे निर्धन, बूढ़े, शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य आघात योग्य समूहों/ परिवारों को इस नियमावली में निर्निर्दिष्ट रीति से तथा मात्रा में मुफ्त खाद्यान्न इस चक्रीय स्टॉक से उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) इस नियमावली के अधिन इस चक्रीय स्टॉक से निकाले गये खाद्यान्नों के लिए संबंधित जन वितरण प्रणाली की दूकान के मालिक को भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला निधि से शीघ्रता से किया जायेगा।

(5) चक्रीय स्टॉक से उपयोग किये गये खाद्यान्नों के लिए जिस दर पर जन वितरण प्रणाली की दूकान को भुगतान किया जाएगा वह, समय-समय पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के परामर्श से, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा निश्चित की जायेगी।

(6) आघातयोग्य वर्गों का कोई व्यक्ति यदि भूखमरी की दशा का सामना करते हुए पाया जाता है तो यथास्थिति मुखिया, वार्ड पार्षद, तत्काल संबंधित जनवितरण प्रणाली की दूकान के मालिक को चक्रीय स्टॉक से निम्नलिखित स्केल पर संबंधित व्यक्ति को खाद्यान्नों की आपूर्ति तुरंत करने हेतु निदेश देगा:

(i) 10 कि०ग्रा० (दस किलोग्राम) एक वयस्क को एक सप्ताह के लिए

(ii) 7 कि०ग्रा० (सात किलोग्राम) एक अवयस्क को एक सप्ताह के लिए

(7) यथास्थिति मुखिया या वार्ड पार्षद, के निदेश पर संबंधित जनवितरण प्रणाली की दूकान का मालिक शीघ्रता से खाद्यान्नों की आपूर्ति संबंधित व्यक्ति को करेगा। चक्रीय स्टॉक से उपयोग किये गये खाद्यान्न के अभिलेख का संधारण जन वितरण प्रणाली की दूकान के मालिक द्वारा किया जायेगा।

(8) संबंधित व्यक्ति को खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के तुरंत पश्चात यथास्थिति, मुखिया या वार्ड पार्षद इसकी सूचना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी को देंगे।

(9) सूचना की प्राप्ति पर अथवा अन्यथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, बिना किसी बिलंब के भूखमरी के कारण के संबंध में संयुक्त जाँच करेंगे तथा संबंधित व्यक्ति को अतिरिक्त खाद्यान्नों की आवश्यकता एवं आजीविका के साधनों का आकलन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में यह संयुक्त जांच 3 (तीन) दिनों के भीतर संचालित कर ली जायेगी।

(10) यदि, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी में से कोई एक, यदि मुख्यालय में उपस्थित न हों, तो उपस्थित पदाधिकारी बिना दूसरे के योगदान करने का इंतजार किये, इस जाँच को संचालित करेगा।

(11) यदि जाँच पड़ताल के उपरान्त, पदाधिकारियों का समाधान हो जाए कि संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को खाद्यान्नों की आगे भी आपूर्ति की आवश्यकता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, जनवितरण प्रणाली की दूकान के मालिक को संबंधित व्यक्ति को इस नियमावली में विहित स्केल पर अतिरिक्त 3 (तीन) सप्ताह के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति करने हेतु तुरत निदेश देगा। इस प्रकार, भूखमरी का सामना कर रहे व्यक्ति को उपर्युक्त रीति से एवं मात्रा में, शुरू में चार सप्ताह के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति की जायेगी।

(12) उपर्युक्त संबंधित व्यक्तियों को खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात् तुरत संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी को सुपुर्द किया जायेगा। अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवेदन में पदाधिकारी, संबंधित व्यक्तियों को आजीविका उपलब्ध कराने/ अन्य कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने और संबंधित व्यक्तियों को 4 (चार) सप्ताह के अतिरिक्त आगे खाद्यान्नों की आपूर्ति करने का आकलन करेंगे।

(13) सभी ऐसे व्यक्तियों का एक अभिलेख, जिन्होंने चक्रीय स्टॉक से खाद्यान्न प्राप्त किया है, पंचायत, नगरीय वार्ड तथा प्रखण्ड स्तर पर क्रमशः मुखिया, वार्ड पार्षद एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा संधारित किया जायेगा।

(14) पदाधिकारियों से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित व्यक्ति को, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से, यदि वह पूर्व में आच्छादित न हो, आच्छादित किया जाय। यदि वह पूर्व से कल्याणकारी योजनाओं के अधीन आच्छादित हो तो जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उन योजनाओं का लाभ बिना किसी असम्यक बिलंब के, संबंधित व्यक्ति को प्राप्त हो जाय। वे इस विषय में आगे की जांच के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित व्यक्ति की समुचित देखभाल हो रही है, अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित कर सकेंगे।

(15) यदि जिला पदाधिकारी का समाधान हो जाय कि संबंधित व्यक्ति की दशा ऐसी है कि उसे एक माह से अधिक के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो वे संबंधित जनवितरण प्रणाली की दूकान के मालिक को खाद्यान्न आपूर्ति करने का निदेश देंगे।

परन्तु जिला पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त होने, जैसा कि नियम 6 के उप-नियम 14 में प्रावधानित किया गया है, के पश्चात् खाद्यान्न की आपूर्ति बंद कर देंगे।

(16) यदि चक्रीय स्टॉक में खाद्यान्न खत्म हो गया हो तो जिला पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी आपूर्ति हेतु बाजार से खाद्यान्नों का क्रय करने का आदेश दे सकेंगे। सभी ऐसे मामलों में ऐसे खाद्यान्नों के लिए भुगतान जिला निधि से भी किया जायेगा।

(17) सभी मुखिया, वार्ड पार्षद, ग्राम पंचायत के सदस्य, तथा अन्य सरकारी कृत्यकरियों से, जिन्हें इस नियमावली के अधीन कोई कार्य सौंपे गये हैं, अपेक्षा की जायेगी कि वे तत्परता के साथ तथा बिना असम्यक् विलंब के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यदि वे जानबूझ कर समनुदेशित कर्तव्यों के निर्वहन में असफल होते हैं तो यह कदाचार के तुल्य होगा तथा सुसंगत अधिनियमों एवं आचरण नियमावली के अधीन उनसे कड़ाई से निपटा जायेगा।

**7. अनुश्रवण तंत्र तथा नोडल प्राधिकार:-** (1) इस योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण पंचायत स्तर पर मुखिया/ग्राम पंचायत के सदस्य, नगरीय वार्ड स्तर पर वार्ड पार्षद, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिलापदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) राज्य स्तर पर इस योजना का अनुश्रवण आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जायेगा।

(3) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी नोडल प्राधिकार होंगे तथा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग नोडल प्राधिकार होगा।

**8. पारदर्शिता:-** (1) इस योजना के क्रियान्वयन में सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी। यदि यह पाया जाता है कि कोई एक स्तर क्रियाशील नहीं है तो उससे ऊपर के स्तर द्वारा इस नियमावली के अधीन नीचे के स्तर को न्यस्त दायित्व स्वयं तत्परता से ग्रहण कर लिया जाएगा।

(2) इस नियमावली के अधीन पारित सभी आदेश तथा ऐसे मामलों का जिनमें सहायता प्रदान की गयी हो, प्रकाशन संबंधित जिला के द्वारा उसके बेवसाइट (Web site) पर, पूर्ण ब्योरे के साथ किया जायेगा।

**9. विवेचना तथा कठिनाइयों का समाधान:-** यदि इस नियमावली के निर्वचन में अथवा इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आपदा प्रबंधन विभाग उसका निर्वचन करने के लिए सक्षम होगा तथा उसके क्रियान्वयन के लिए अनुदेश जारी करेगा। ऐसे सभी विषयों में उस विभाग का विनिश्चय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
व्यास जी,  
प्रधान सचिव।

25 जुलाई 2011

सं०-1/आ०प्र०यो०-12/2010-2389/आ०प्र०, अधिसूचना संख्या 2388, दिनांक 25 जुलाई 2011 का निम्नलिखित अंगरेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
व्यास जी,  
प्रधान सचिव।

*The 25<sup>th</sup> July 2011*

### **Shatabdi Anna Kalash Yojana Rules, 2011**

No. 2388/DM, dated 25<sup>th</sup> July 2011—WHEREAS it is the duty of the state to prevent incidence of starvation amongst the indigent, old, infirm, widows, destitute and other vulnerable sections of people living in the State, and to ensure the vulnerable sections of society to have easy access to food in case they face conditions of starvation; And, whereas the vulnerable sections of Society have rightful claim over ownership and control of the material resources of the community. Therefore the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules under Article 39(b) of the Constitution of India:-

**(1) Short title, extent and Commencement:**—These Rules may be called the “Shatabdi Anna Kalash Yojana Rules, 2011”.

**(2)** It shall extend to the whole of the State of Bihar.

**(3)** It shall come into force with immediate effect.

**2. Definition:—(1)** In these Rules, unless otherwise requires in the context-

- (i) **“Anchal Adhikari”** means the officer designated as such by the State Government.
- (ii) **“Block Development Officer”** means the officer as such designated by the State Government.
- (iii) **“Department of Disaster Management”** means the Disaster Management Department of the State.
- (iv) **“Department of Food and Consumer Protection”** means the Department of Food and Consumer Protection of the State Government of Bihar.
- (v) **“Department of Social Welfare”** means the Department of Social Welfare of the State Government.
- (vi) **“District Magistrate”** means the District Magistrate and Collector of a district.
- (vii) **“Fund”** means the Funds constituted under the Yojana.
- (viii) **“Mukhiya”** means the person working as mukhiya of a gram panchayat under the Bihar Panchayati Raj Act.
- (ix) **“Rules”** means the Shatabdi Anna Kalash Yojana Rules, 2010.
- (x) **“State Government”** means the Government of Bihar.

- (xi) **Ward Councilor** means the councilor of a municipal ward as defined in the Bihar Municipality Act, 2007.
- (xii) **“Welfare Schemes”** means the welfare schemes of the Central and State Government under implementation in the State of Bihar by various departments of the State Government.
- (xiii) **“Yojana”** means the Shatabdi Anna Kalash Yojana.
- (2) Words and expressions not defined but used in these Rules shall have the same meaning as they are understood in common parlance in the State of Bihar.

### **3. Constitution and Management of Funds:-**

- (1) A Fund in the name and style of State ShatabdiAnna Kalash Fund at the State level, called the State Fund, and District ShatabdiAnna Kalash Fund in all districts, called the District Fund, shall be constituted for the purpose of making payments for the food grains provided to the vulnerable sections under the yojana.
- (2) All moneys allocated by the State Government under the yojana shall be kept in the Funds. General Public may also be encouraged to make contributions, in cash, to the funds.
- (3) The State Executive Committee of the State Disaster Management Authority shall administer the State Fund. However, the Secretaries/Principal Secretaries of Food and Consumer Affairs and Social Welfare Departments shall be the special invitees in such meetings of the Committee.
- (4) The District Disaster Management Authority shall administer the District Fund. However, the District Supply Officer/Additional District Magistrate (Supply) and District Programme Officer shall be the special invitees in such meetings of the Authority.
- (5) The State Government shall allocate an initial corpus of Rs 10 crore in the State Fund and shall make annual allocations, in consultation with the State Executive Committee. The allocations so made shall form part of the annual non-plan budget of the Disaster Management Department.
- (6) Allocation shall be made to the Districts Funds in installments out of the State Fund in accordance with a criteria decided by the State Executive Committee. However, the next installment shall be released only when the 75% of the previous installment has been spent.

### **4. Account and Audit of the Funds:**

- (1) The Funds shall be kept in a savings bank account opened in the name of the respective Funds in a nationalized bank and the interest accrued there from shall also form part of the Funds.
- (2) The accounts of the State and District Funds shall be maintained by the Disaster Management Department and concerned District Disaster Management Authority respectively.
- (3) The Funds shall be audited annually by the Audit wing of the Finance Department and report shall be submitted to the concerned offices and Department of Finance of the State Government.

### **5. Duty of Mukhiya, Ward members, ward commissioners and other Panchayat level functionaries under these rules:**

- (1) It shall be the duty of the Mukhiyas, Ward Councilors, Panchayat Ward members and other Panchayat level functionaries in the village areas and concerned ward councilors in urban areas to be vigilant about the

availability of food to the indigent, old, infirm, widows, destitute and other vulnerable sections/households residing within their respective jurisdiction. They shall keep special vigilance on the availability of food to those vulnerable households who are resourceless and have no means of livelihood or have been rendered incapable, permanently or temporarily, by circumstances beyond their control, of earning their livelihood

- (2) The panchayat level functionaries referred to in these rules shall include Angan Wadi Workers, ASHA workers, Panchayat Sachivs, revenue karmacharis, village level agriculture workers etc.
- (3) In keeping the vigilance, Mukhiya, ward Councilors and Panchayat ward members, as the case may be, shall have right to seek the assistance of the government field functionaries working in their respective jurisdictions. They may also seek assistance from civil society organizations.
- (4) Every information reaching the Mukhiyas, ward Councilors, ward members or the aforesaid functionaries, as the case may be, regarding any vulnerable person/household facing starvation conditions, shall be promptly enquired by the concerned and a report shall be submitted to the Mukhiya, Ward Councilors or the Block Development Officer, as the case may be.

**6. Shatabdi Anna Kalash Yojana**

- (1) The Food and Consumer Protection Department, in consultation with the Disaster Management Department and the concerned District Magistrate, shall maintain a revolving stock of one quintal wheat/rice at a designated Public Distribution system shop (PDS shop) in every Panchayat in each district of the State. In urban area the District Magistrate shall mark such shopkeeper of specified public distribution system shop where revolving food grains stock may be stored.
- (2) The payment for lifting of the revolving stock from the godowns of the State Food Corporation shall be made by the concerned PDS shop owner.
- (3) Food grains from this revolving stock shall, in the manner and quantities specified under these Rules, be made available, free of cost, to the indigent, old, infirm, widows, destitute and other vulnerable sections/households facing conditions of starvation.
- (4) The payments to the concerned PDS shop owner for the food grains taken out from the revolving stock under these rules shall be made promptly from the District Fund by the respective District Magistrates.
- (5) The rates at which the PDS shop shall be paid for the food grains utilized from the revolving stock shall be determined, from time to time, by the Disaster Management Department in consultation with the Food and Consumer Affairs Department.
- (6) In case any person of the vulnerable section is found facing the condition of starvation, the Mukhiya or the ward counciloner, as the case may be, shall immediately direct the PDS shop owner to supply food grains from the aforesaid revolving stock to the concerned person at the following scale:
  - (i) 10 kg (ten kilogram) for one week to an adult.
  - (ii) 7 kg (seven kilogram) for one week to a child.

- (7) Upon the direction of the Mukhiya or the ward councilor, as case may be the PDS shop owner shall supply the food grains promptly to the concerned person. The PDS shop owner shall maintain the record of the food grain utilized from the revolving stock.
- (8) The Mukhiya or the ward councilor, as the case may be, shall, immediately after ensuring supply of the food grain as above to the concerned person, inform the Block Development Officer and the Anchal Adhikari.
- (9) The Block Development Officer and the Anchal Adhikari, upon receipt of the information or otherwise, shall without delay make a joint enquiry about the causes of starvation and assess the further need of food grain and means of livelihood of the concerned person. In any case, the joint enquiry shall be conducted within 3 (three) days.
- (10) However, if any one of the Block Development Officer or the Anchal Adhikari is not present at the headquarters, the officer present shall conduct the enquiry without waiting for the other to join him.
- (11) If upon the enquiry, the Officer(s) is satisfied that the person(s) concerned need further supply of food grains, the Block Development Officer shall immediately direct the PDS shop owner to supply food grains for 3 (three) more weeks at the scale prescribed in these rules. Thus, to begin with the persons facing starvation shall be provided with the supply of food grains for 4 (four) weeks in the aforesaid manner and quantity.
- (12) The joint report shall, immediately after ensuring supply of the food grain as above to the concerned persons, be submitted to the Sub Divisional Officer and the District Magistrate. In the report, the Officer(s) shall, inter alia, suggest the measures required to provide means of livelihood and/or cover of welfare schemes to the concerned person(s) and also shall do assessment of further supply of food grains to the concerned persons beyond 4 (four) weeks.
- (13) A record of all such persons to whom food grains have been distributed from the revolving stock shall be maintained at the Panchayat, Municipal ward and Block level by the Mukhiya Ward Councilor and the Block Development Officer respectively.
- (14) The District Magistrate, upon receipt of the joint enquiry report from the Officer(s), shall ensure that the concerned person, if not covered earlier, is covered under the welfare schemes of the Government. If the person is covered under any of the welfare schemes, the District Magistrate shall ensure that delivery of benefits of such schemes to that person is made without undue delay. He may direct the sub divisional officer to make further enquiry in the matter and ensure that the concerned person is taken care of.
- (15) If the District Magistrate is satisfied that the condition of the concerned person is such that he should be provided with food for a period longer than one month, he shall direct the PDS owner to so supply the food grain to that person. Provided that the District Magistrate shall stop supply of the food grain to person once the delivery of benefits of the welfare schemes of the Government is made to the concerned person as provided in the sub rule 14 of rule 6.



- (16) In case, the food grain in the revolving stock is diminished, the District Magistrate or Sub divisional Officer shall order purchase of food grain from the market for supply. In all such cases payment for such food grains shall be also made from the District Fund.
- (17) All Mukhiyas, ward Councilors and Panchayat ward members and other government functionaries who have been entrusted with any task under these rules shall be expected to discharge their duties with promptness and undue delay. If they willfully fail to discharge the assigned duties, it shall tantamount to misconduct and they shall be strictly dealt under relevant Acts and Conduct Rules.

**7. Monitoring Mechanism and Nodal Authorities:**

- (1) The implementation of this yojana shall be monitored at Panchayat level by the Mukhiya, municipal ward level by the ward councilor, at Block level by the Block Development Officer, at Subdivision level by the Sub Divisional Officer and at the district level by the District Magistrate.
- (2) The monitoring of the yojana at the State level shall be made by the Disaster Management Department.
- (3) The District Magistrate shall be nodal authority at the district level and the Disaster Management Department shall be the nodal authority at State level.

**8. Transparency:**

- (1) Complete transparency shall be maintained at all levels in the implementing the schemes. If it is found that any level is not functional, the next higher level shall promptly take upon itself the responsibility entrusted to the lower level under these rules.
- (2) All orders passed under these rules and all cases in which assistance has been rendered shall be placed on the website of the concerned district with full details.

**9. Interpretation and Removal of difficulties:**

- (1) If any difficulty arises in the interpretation of these rules or implementation of the yojana, the Disaster Management Department shall be competent to interpret it and issue instruction for its implementation. The decision of this department in all such matters shall be final and binding.

By Order of the Governor of Bihar,  
 VYAS JI,  
*Principal Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
 बिहार गजट (असाधारण) 364-571+500-डी0टी0पी0।  
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>